



प्रभारी

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P. O.— 450

Km.— 30

Dept.— 200

CPB.— 220

भा०

८२

१२/१०४

सं. 444]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2004/आश्विन 20, 1926

No. 444]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2004/ASVINA 20, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2004

(आयकर)

सा.का.नि. 667(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मलेशिया सरकार के मध्य अनुबंध करार उक्त करार के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत उक्त करार को प्रवृत्त करने के लिए उनके मंत्रालय कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को अधिसूचित करने के उपरान्त 14 अगस्त, 2003 को प्रवृत्त हो गया है :

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त करार के सभी प्रावधानों को भारत संघ में प्रवृत्त किया जाएगा।

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए
मलेशिया की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

मलेशिया की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार निष्पत्र करने की इच्छा से और दोनों
देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से,

निम्नानुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद—1

वैयक्तिक कार्यक्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. जिन करों पर यह करार लागू होगा वे निम्नलिखित के अनुसार हैं :

(क) मलेशिया में :-

(i) आयकर ; और

(ii) पेट्रोलियम आयकर ;

(जिन्हें इसके बाद "मलेशियाई कर" कहा जाएगा);

(ख) भारत में,

आयकर पर अधिभार सहित आयकर ;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)।

3. यह करार किसी मिलते-जुलते अथवा पर्याप्त रूप से एक समान उन करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो परिवर्तन उनके अपने-अपने कराधान कानूनों के अंतर्गत किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "मलेशिया" पद का अर्थ है - मलेशिया संघ के राज्य क्षेत्र, मलेशिया के राज्यक्षेत्रीय समुद्र और राज्यक्षेत्रीय समुद्र का समुद्र तल और अवमृदा और इसमें मलेशिया के राज्यक्षेत्रीय समुद्र की सीमा से बाहर फैला हुआ कोई भी क्षेत्र तथा ऐसे किसी क्षेत्र का समुद्र तल और अवमदा, जिसे मलेशिया के कानून के अंतर्गत और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी ऐसे क्षेत्र के रूप में नामोदिष्ट किया गया है या बाद में नामोदिष्ट किया जा सकता है जिस पर प्राकृतिक संसाधनों, चाहे जीवित अथवा अजीवित, के पूर्वक्षण और दोहन के प्रयोजनार्थ मलेशिया के प्रभुसत्तासम्बन्ध अधिकार हैं;

(ख) "भारत" का अभिप्राय है - भारत का राज्यक्षेत्र तथा उसमें इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिनमें भारतीय कानून के अनुसार और अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्बन्ध अधिकार अन्य अधिकार अंतर्गत अथवा क्षेत्राधिकार हैं;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य" का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार मलेशिया अथवा भारत है ;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत किसी कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;

(ङ) "सहाय प्राधिकारी" पद का अभिप्राय है :-

- (i) मलेशिया के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; और
- (ii) भारत के मामले में, केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान, अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतार हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अलवा यदि उसका दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ।

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

(छ) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान, उक्त संविदाकारी राज्य के बीच ही चलाए जाते हों;

(ज) “राष्ट्रिक” पद का अर्थ है :

- (i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता अथवा नागरिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;
- (ii) कोई विधिक व्यक्ति, मानीदारिता, संस्था, कोई अन्य सत्ता जिसे इस प्रकार की अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

(झ) “व्यक्ति” पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है :

(ञ) “कर” पद का अर्थ है, संदर्भ की अपेक्षानुसार, मलेशियाई कर अथवा भारतीय कर किन्तु इसमें उन करों के संबंध में किसी भूल या छूक के बारे में अदा की जाने वाली कोई ऐसी राशि शामिल नहीं है जिन पर यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में अधिरोपित किसी अर्थदण्ड अथवा जुर्माने की घोतक हो।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए जाने में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद - 5 स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए “स्थायी संस्थापन” पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहां से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा इमारती लकड़ी अथवा अन्य वानिकी उत्पाद सहित प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (छ) कोई फार्म अथवा बाग ;
- (ज) कोई विक्रय बाजार ;
- (झ) कोई माल गोदाम ;
- (ञ) कोई भवन स्थल अथवा संरचना प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना जो नौ महीने से अधिक अवधि तक अस्तित्व में रहे ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूखना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना :

(ङ) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

4. किसी संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा यदि वह किसी संरचना, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना के संबंध में उस दूसरे राज्य में नौ महीने से अधिक अवधि तक ऐसा कोई पर्यवेक्षकीय कार्यकलाप चलाता हो जिसे उस राज्य में चलाने के लिए जिम्मेदारी ली जा रही है ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा किसी अन्य एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो उक्त उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को आदतन :-

(क) उस उद्यम के नाम से प्रथमोल्लिखित राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकारण का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद तक ही सीमित न हों ; अथवा

(ख) उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हो किन्तु वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में उक्त उद्यम से संबंधित ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से आर्डरों की पूर्ति करता हो ; अथवा

(ग) वह उस उद्यम के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में उस उद्यम से संबंधित ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का विनिर्माण अथवा संसाधन करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामले छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि वह दूसरे राज्य के राज्य-क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा किसी ऐसे स्वतंत्र हैसियत वाले अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम का मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा, कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति उनके कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों ।

तथापि, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो ऐसा व्यक्ति एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा यदि उक्त एजेंट और उद्यम के बीच समव्यवहार कुछ दूरी की स्थितियों के तहत नहीं किए गए हों ।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2. "अचल सम्पत्ति" पद उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, तेल अथवा गैस का कुआं, खदान और इमारती लकड़ी अथवा अन्य वानिकी-उत्पाद सहित प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नौकाएं और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके उतने लाभों पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभाशों के निर्धारण में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार और उनके प्रतिबंधों की शर्तों के अधीन उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और

सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों ।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6. जहाँ लाभों में आय की ऐसी मर्दे शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जलयानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में उस उद्यम द्वारा जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों पर उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों या वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों का अभिप्राय पैराग्राफ 1 में वर्णित किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ होंगे जो जलयानों अथवा वायुयानों के मालिकों अथवा पट्टाधारकों अथवा अवक्रेताओं द्वारा वाहित यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल का क्रमशः समुद्री मार्ग अथवा वायु मार्ग द्वारा परिवहन से प्राप्त होंगे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

- (क) अन्य उदामों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री ; और
- (ख) ऐसे परिवहन से सीधे तौर पर संबंधित किसी कार्यकलाप से अनुषंगी जलयानों अथवा वायुयानों का किराया ।

3. पैराग्राफ 1 में वर्णित एक संविदाकारी राज्य को किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के संबंध में प्रयुक्त आधानों (आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलरों, नौकाओं और अन्य संबंधित उपकरण सहित) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी पूल, संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन अभिकरण में भागीदारिता से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

6. पैराग्राफ 1 में वर्णित एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त ऐसे अभिलाम जो उक्त उद्यम द्वारा अपने स्वामित्व में रखे जाने वाले अथवा प्रचालित किए जाने वाले जलयानों, वायुयानों अथवा आधानों के अंतरण से प्राप्त होते हैं, जिनसे प्राप्त आय केवल उसी राज्य में कराधेय होती है, उस पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 9 सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 10 लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य मेंउत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ (2) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :-

(क) मलेशिया के मामले में :

(i) मलेशिया की सरकार ;

(ii) उक्त राज्य की सरकार ;

(iii) दि बैंक नेगारा मलेशिया ;

(iv) स्थानीय प्राधिकरण ;

(v) सांविधिक निकाय ; और

(vi) दि एक्सपोर्ट - इम्पोर्ट बैंक आफ मलेशिया बरहाद (एक्जिम बैंक);

(ख) भारत के मामले में :-

(i) सरकार ;

(ii) राजनैतिक उप-प्रभाग ;

(iii) सांविधिक निकाय ;

(iv) स्थानीय प्राधिकरण ;

(v) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ;

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक ;

(vii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ;

(viii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ;

(ix) राष्ट्रीय आवास बैंक ;

(x) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक ;

(xi) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई) ;

(ग) कोई अन्य संरथाएं जिन पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हो जाए ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का आशय प्रत्येक इकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे ३५ क्रणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा क्रणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें देसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा क्रणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज अर्जित

हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋणदावे के बारे में व्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला वह राज्य स्वयं अथवा उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई सांविधिक निकाय अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह व्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, व्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई व्याज की रकम, उस रकम ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के अधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - सिनेमा फिल्में अथवा दूरदर्शन या आकाशवाणी से प्रसारण के संबंध में प्रयोग के लिए पुनर्निर्माण के किसी माध्यम पर रिकार्डिंग, सहित किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट किसी पेटेंट, ड्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान जानकारी, कम्प्यूटर साप्टवेयर प्रोग्राम, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियाँ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अदा करने की जिम्मेदारी निर्माई गई हो और ऐसी रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का अधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद - 13

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की जाती है, उस दूसरे राज्य में कराधेय होगी।

2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं की फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा। किन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का अर्थ तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं के उपबंध सहित किसी प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाओं को करने के प्रतिफल में किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं किन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में वर्णित सेवाओं के लिए अदायगियां सम्मिलित नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं की फीस का हितभागी स्वामी , जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 और 14 के उपबंध, यथास्थिति, लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो , जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच इसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी भी वजह से अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की राशि उस राशि से बढ़ जाती है, जिस पर इस प्रकार के संबंधों के अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदागियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों से प्राप्त आय केवल उस राज्य में ही कराधेय होगी । तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है ।

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने वाली या समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन के लिए हों , तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो दूसरे राज्य में उसको अपने निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ; अथवा

(ग) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक या तो उस राज्य के किसी ऐसे निवासी से प्राप्त किया जाता है अथवा किसी ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है जो उस राज्य में अनिवासी किसी व्यक्ति द्वारा उस राज्य में रखा जाता है और जो दोनों में से किसी भी मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष में दो हजार अमेरिकी डालरों के बराबर की राशि के मूल्य से अधिक हो जाती है ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा काय-चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन अथवा उसके बराबर की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे निवासी अथवा स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा दर्तन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उदास द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त पारिश्रमिक अथवा लाभों पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण अथवा साविधिक निकाय की लोक निधियों द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, पूर्णतया अथवा पर्याप्त रूप से सहायता की जाती हो।

अनुच्छेद - 18

गैर- सरकारी पेंशन और वार्षिकियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य में पिछले नियोजन के लिए प्राप्त किसी पेंशन और अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक पर अथवा उसमें उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की जाने वाली वार्षिकी पर केवल दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2. “वार्षिकी” पद से जीवन काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या अधिनिश्चित समयावधि के दौरान धनराशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगी करने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत आवधिक रूप में निश्चित समय पर अदायगी योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय द्वारा किसी व्यस्ति को उस राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ।

(ख) तथापि; ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यस्ति उस राज्य का निवासी है, जो :

- (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा
- (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय द्वारा सृजित कोष द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यस्ति को उस राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

3. अनुच्छेद 15, 16, और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय द्वारा किए जा रहे किसी व्यापार अथवा कारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी

1. कोई व्यस्ति जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था और जो दूसरे राज्य में निम्नलिखित के रूप में मात्र अस्थायी तौर पर उपस्थित है :

(क) उक्त दूसरे राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अथवा अन्य इसी तरह की मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में ;

(ख) एक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में ; अथवा

(ग) दोनों राज्यों में से किसी एक की सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा धर्मर्थ संगठन से अथवा दोनों राज्यों में से किसी की सरकार द्वारा लागू किए गए तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के मुख्य प्रयोजन के लिए अनुदान, मत्ता अथवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में ;

उसे निम्नलिखित पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी -

- (i) उसके भरण -पोषण, शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ भेजी गई समस्त धनराशियाँ ;
- (ii) ऐसे अनुदान, भत्ते या पुरस्कार की राशि ; और
- (iii) उस दूसरे राज्य में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त कोई पारिश्रमिक जो दो हजार अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की राशि के बराबर से अधिक न हो, बशर्ते कि सेवाएं उसके अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के लिए निष्पादित की जाती हैं अथवा उसके भरण-पोषण के लिए आवश्यक हैं ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो । तथापि, किसी भी हालत में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (iii) के लाभ दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार सात वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 21

अध्यापक और शोध-अध्येता

1. कोई ऐसा व्यष्टि जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था और जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य इसी प्रकार की शैक्षिक संस्था के नियंत्रण पर ऐसी शैक्षिक संस्था में मात्र अध्यापन अथवा शोध-कार्य अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दो वर्ष की अनधिक अवधि के लिए दूसरे राज्य का दौरा करता है तो ऐसे अध्यापन अथवा शोध-कार्य के लिए उसे प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी जिस पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है ।

2. यह अनुच्छेद शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मुख्यतया किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से पहले तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस संविदाकारी राज्य में एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दें, जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्टतया उल्लेख नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी सिवाय उन मामलों के जहां ऐसी आय दूसरे संविदाकारी राज्य के लोतों से प्राप्त होती है वहां इस पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित राज्यों में आय पर कराधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों में जहां इस करार में उनके विपरीत प्रावधान किए जाएं ।

2. मलेशिया के मामले में दोहरे कराधान का निम्न प्रकार से अपाकरण किया जाएगा :-

मलेशिया को छोड़कर किसी भी देश में देय कर के मलेशिया कर के प्रति क्रेडिट के रूप में छूट के संबंध में मलेशिया के कानूनों के अव्यधीन भारत में प्राप्त की गई आय के संबंध में मलेशिया के किसी निवासी द्वारा भारत के कराधान कानूनों के अंतर्गत भारत में अदा किए गए कर को उस आय के संबंध में मलेशिया में देय कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी । जहां ऐसी आय भारत की निवासी किसी कम्पनी द्वारा मलेशिया की निवासी किसी कम्पनी को अदा किया गया कोई लाभांश है और जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 10 प्रतिशत वॉटिंग शेयर का मालिक हो वहां उसकी उस आय के संबंध में उस कम्पनी द्वारा भारत में अदा किए गए कर को क्रेडिट ध्यान में रखेगा जिसमें से उक्त लाभांश अदा किया जाता है । तथापि, उक्त क्रेडिट मलेशियाई कर के उस भाग से अधिक नहीं होगा (जो क्रेडिट दिए जाने के पहले संगणित किया जाता है) जो आय की ऐसी मद से उद्भूत होता है ।

3. पैराग्राफ 2 के प्रयोजनार्थ "भारत में अदा किया गया कर" पद में वह कर शामिल हुआ माना जाएगा जो भारत के कानूनों के अंतर्गत और इस करार के अनुसार भारत में स्रोतों से प्राप्त किसी आय पर देय होता यदि उस आय पर इस करार के उपबंधों के अनुसार और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कानूनों के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहनों, जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को लागू हो, अथवा किन्हीं ऐसे उपबंधों के अनुसार, जिन्हें उक्त कानूनों के संशोधन में अथवा उनके अतिरिक्त, भारत में बाद में लागू किया जा सकता है, भारतीय कर से कम दर पर कर नहीं लगाया जाता अथवा उससे छूट नहीं दी जाती । जहां तक कि उन पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस बात पर सहमति हो जाती है कि वे पर्याप्त रूप से एवं ऐसी प्रकृति के हैं ।

4. भारत के मामले में, दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार मलेशिया में कर लगाया जा सकता है, भारत उस निवासी की आय पर मलेशिया में अदा किए गए कर की राशि के बराबर की राशि को कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा। यह कर प्रत्यक्षतः अथवा स्रोत पर कटौती द्वारा दिया गया हो । ऐसी राशि कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी (जो कटौती दिए जाने से पहले संगणित की जाती है) जो इस आय से उद्भूत होती है जिसपर मलेशिया में कर लगाया जा सकता है ।

5. पैराग्राफ 4 के प्रयोजनार्थ 'मलेशिया में अदा किया गया कर' पद में वह कर शामिल हुआ माना जाएगा जो मलेशिया के कानून के अंतर्गत और इस करार के अनुसार मलेशिया में स्रोतों से प्राप्त किसी आय पर देय होता यदि उस आय पर इस करार के उपबंधों के अनुसार और मलेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मलेशियाई कानूनों के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहनों, जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को लागू थे अथवा किन्हीं ऐसे उपबंधों के अनुसार, जिन्हें उन कानूनों के संशोधनों में अथवा उनके अतिरिक्त, बाद में मलेशिया में लागू किया जा सकता है, मलेशियाई कर से कम दर पर कर नहीं लगाया जाता अथवा उससे छूट नहीं दी जाती जहां तक कि उनपर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस बात पर सहमति हो जाती है कि वे पर्याप्त रूप से एक जैसी प्रकृति के हैं।

अनुच्छेद - 24

समव्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षा को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जा रहे अथवा लगाए जा सकने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से मिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में एक समान कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कठौतियों की मंजूरी दे जो यह अपने निवासियों को देता है। इसके अतिरिक्त इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के समरूप उद्यम के लाभों पर लगाया जाता है और न ही इसका अर्थ इस करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना माना जाएगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से मिन्न अथवा अपेक्षाकृत भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लागू हो अथवा लागू हो सकती हो।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य को उस राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने राष्ट्रिकों तक कर प्रोत्साहनों को सीमित रखने से रोकना है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद का तात्पर्य वे कर हैं जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के अनुसार नहीं है तो वह उन्‍हें राज्यों के कराधान कानूनों में उपबंधों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दस्ति से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।
3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो।
4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के अपवंचन अथवा परिहार को रोकने के लिए अथवा उनका पता लगाने के लिए आवश्यक हो, इस प्रकार से आदान-प्रदान की गई सूचना को गुप्त माना जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय, प्रशासनिक निकाय अथवा पुनरीक्षा प्राधिकारी भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो जो इस करार की विषय-वस्तु हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे किन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्रवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।
2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसे विवरणों की सम्पार्दी करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं ;

(ग) ऐसी सूचना की सम्पार्दी करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो ।

अनुच्छेद - 27

राजनयिक और कौंसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 28

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना के तीस दिन बाद लागू होगा ।

3. इस करार के उपबंध निम्नानुसार प्रभावी होंगे :

(क) मलेशिया में :

(i) मलेशियाई कर के संबंध में, पेट्रोलियम आयकर को छोड़कर, जिस वर्ष में यह करार लागू किया जाता है उसके अगले कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य कर के लिए ;

(ii) पेट्रोलियम आय कर के संबंध में, जिस वर्ष में यह करार लागू किया जाता है उसके अगले द्वितीय कैलेण्डर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य कर के लिए ;

(ख) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू किया जाता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में।

4. आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए मलेशिया सरकार तथा भारत सरकार के बीच यह करार, जिस पर नई दिल्ली, भारत में 1976 अक्टूबर के 25वें दिन हस्ताक्षर किए गए थे, तब निष्प्रभावी हो जाएगा जब इस करार के उपबंध पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनुसार प्रभावी हो जाएंगे।

अनुच्छेद - 29

समापन

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा किन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद शुरू होने वाले किसी माघ्यमों से इस करार के समापन का लिखित नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में प्रभावी नहीं होगा :

(क) मलेशिया में :

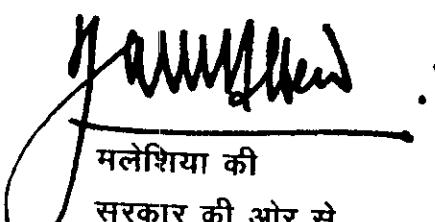
- (i) मलेशियाई कर के संबंध में, पेट्रोलियम आयकर को छोड़कर, जिस वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के प्रभार्य कर के लिए;
- (ii) पेट्रोलियम आय कर के संबंध में, जिस वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले द्वितीय कैलेण्डर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के प्रभार्य कर के लिए;

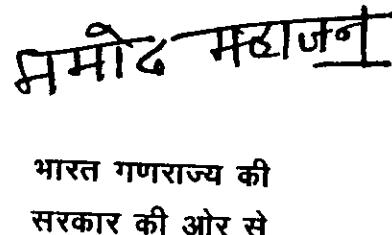
(ख) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष दो हजार एक के माह के दिन मलय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पत्र किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस करार की व्याख्या करने और इसे लागू करने में किसी विवाद के होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।


मलेशिया की
सरकार की ओर से


भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच इस करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरियों ने सहमति व्यक्त की है कि निम्नलिखित उपबंध इस करार के अभिन्न अंग होंगे ।

यह समझा जाता है :

1. करार के प्रयोजनार्थ “वित्तीय वर्ष” जहां कहीं भी यह प्रकट होता है उसका अर्थ

निम्नलिखित होगा :

(i) मलेशिया के मामले में, आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 20 द्वारा यथा-निर्धारित

अर्थ ;

(ii) भारत के मामले में, “पिछला वर्ष” जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिमाणित किया गया है ।

2. अनुच्छेद -3 के पैराग्राफ 1 (ज) के संदर्भ में, कर में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के लिए किसी अर्थ-दण्ड अथवा जुर्माने के रूप में देय होती है जिस पर यह करार लागू होता है और जो उन करों के संबंध में लगाए गए किसी अन्य अर्थदण्ड अथवा जुर्माने की घोतक है ।

3. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 7 के संदर्भ में, “कुछ दूरी की शर्तों” का अर्थ वे शर्तें हैं जो दोनों उद्यमों के बीच उनकी वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में लगाई गई होती या अधिरोपित की गई होती और जो उन शर्तों से भिन्न नहीं होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती अथवा अधिरोपित की गई होती ।

4. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में, इस पैराग्राफ का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इससे निवासी देश को इस अनुच्छेद के अंतर्गत आय पर भी कर लगाने से रोकना है ।

5. अनुच्छेद 28 के उप-पैरा 3 (क) (i) और (ii) तथा अनुच्छेद 29 के उप-पैरा 3 (क) (i) और (ii) के संदर्भ में, “निर्धारण वर्ष” का अर्थ आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 2 के अंतर्गत निर्धारित किया गया अर्थ है ।

में वर्ष दो हजार एक के माह के दिन मलय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पत्र किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । इस करार की व्याख्या करने और इसे लागू करने में किसी विवाद के होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

[Signature] :
मलेशिया को
सरकार की ओर से

[Signature]

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
[अधिसूचना सं. 257/2004/फा. सं. 506/123/84-वि.क.प्र.]
पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2004

(Income Tax)

G. S. R. 667(E).— Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to Taxes on income has come into force on the 14th August, 2003, on the notification by both the Contracting States to each other, under Article 28 of the said Agreement, of the completion of the procedures required by their respective laws for bringing into force of the said Agreement :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

Annexure

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

THE GOVERNMENT OF MALAYSIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic co-operation between the two countries, have agreed as follows :

Article 1**PERSONAL SCOPE**

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2**TAXES COVERED**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed by a Contracting State or its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. The taxes which are the subject of this Agreement are:
 - (a) in Malaysia -
 - (i) the income tax; and
 - (ii) the petroleum income tax;
(hereinafter referred to as "Malaysian tax");
 - (b) in India -
the income tax including any surcharge thereon;
(hereinafter referred to as "Indian tax").
3. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of important changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "Malaysia" means the territories of the Federation of Malaysia, the territorial waters of Malaysia and the sea-bed and subsoil of the territorial waters, and includes any area extending beyond the limits of the territorial waters of Malaysia, and the sea-bed and subsoil of any such area, which has been or may hereafter be designated under the laws of Malaysia and in accordance with international law as an area over which Malaysia has sovereign rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources, whether living or non-living;
 - (b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law and the U.N. Convention on the Law of the Sea;
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Malaysia or India as the context requires;
 - (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
 - (e) the term "competent authority" means -
 - (i) in the case of Malaysia, the Minister of Finance or his authorised representative; and
 - (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
 - (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
 - (h) the term "national" means -

- (i) any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State; and
- (ii) any legal person, partnership, association and any other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "person" includes an individual, a company, and any other body of persons;

(j) the term "tax" means Malaysian tax or Indian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of a default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes.

2. In the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which this Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the tax laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources including timber or other forest produce;
- (g) a farm or plantation;
- (h) a sales outlet;
- (i) a warehouse;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project which exists for more than nine months;

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other State for more than nine months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other State.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than a broker, general commission agent or any other agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State, if such a person:

- (a) has, and habitually exercises in the first-mentioned State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise; or

(c) manufactures or processes in the first-mentioned State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, such a person shall not be considered an agent of an independent status if the transactions between the agent and the enterprise were not made under arm's length conditions.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil or gas wells, quarries and other places of extracting natural resources including timber or other forest produce. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only on so much thereof as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including:
 - (a) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises; and
 - (b) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

5. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the alienation of ships, aircraft or containers owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

Article 9**ASSOCIATED ENTERPRISES**

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10**DIVIDENDS**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment in that other State, or fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

(a) in the case of Malaysia:

- (i) the Government of Malaysia;
- (ii) the government of the state;
- (iii) the Bank Negara Malaysia;

- (iv) the local authorities;
- (v) the statutory bodies; and
- (vi) the Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank);

(b) in the case of India:

- (i) the Government;
- (ii) the political subdivisions;
- (iii) the statutory bodies;
- (iv) the local authorities;
- (v) the Export-Import Bank of India (EXIM Bank);
- (vi) the Reserve Bank of India;
- (vii) the Industrial Finance Corporation of India;
- (viii) the Industrial Development Bank of India;
- (ix) the National Housing Bank;
- (x) the Small Industries Development Bank of India; and
- (xi) the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI);

(c) any other institutions as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a

fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic or scientific work including cinematograph films or recordings on any means of reproduction for use in connection with television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, know-how, computer software programme, secret formula or process, or any industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying such royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Fees for technical services arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the fees for technical services , the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees for technical services.

3. The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Article 14 and Article 15 of this Agreement.

4. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the fees for technical services are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying the fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the fees for technical services was incurred, and such fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the fees for technical services paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall only apply to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may also be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

- (b) if his stay in the other State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State; or
- (c) if the remuneration for his services in the other Contracting State is either derived from a resident of that State or borne by a permanent establishment or fixed base which a person not resident in that State has in that State and which, in either case exceeds in value an amount equivalent to two thousand U.S. dollars in the fiscal year concerned.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State; and
- (c) the remuneration is not borne by a resident or permanent establishment or fixed base which the employer has in the other State or by a person carrying on independent personal services in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration or profits derived from activities exercised in a Contracting State if the visit to that State is directly or indirectly supported wholly or substantially from the public funds of the other Contracting State, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof.

Article 18

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, any pension and other similar remuneration for past employment or any annuity arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "annuity" includes a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or political subdivision or a local authority or statutory body thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the recipient is a resident of that other State who:
 - (i) is a national of that other State; or
 - (ii) did not become a resident of that other State solely for the purpose of performing the services.

2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State, political subdivision, local authority or statutory body thereof shall be taxable only in that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pension in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by a Contracting State, a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof.

Article 20**STUDENTS AND TRAINEES**

1. An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and is temporarily present in the other State solely:

- (a) as a student at a recognised university, college, school or other similar recognised educational institution in that other State;
- (b) as a business or technical apprentice; or
- (c) as a recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study, research or training from the Government of either State or from a scientific, educational, religious or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of either State,

shall be exempt from tax in that other State on -

- (i) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, study, research or training;
- (ii) the amount of such grant, allowance or award; and
- (iii) any remuneration not exceeding an amount equivalent to two thousand U.S. Dollars per annum in respect of services in that other State provided the services are performed in connection with his study, research or training or are necessary for the purposes of his maintenance.

2. The benefits in respect of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken. However, in no event shall any individual have the benefits of paragraph (iii) of this Article for more than seven consecutive years from the date he first arrived for such purpose in that other Contracting State.

Article 21**TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS**

1. An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college or other similar educational institution, visits that other State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research which is subject to tax in the first-mentioned Contracting State.
2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the immediately preceding fiscal year before he visits the other Contracting State.

Article 22**OTHER INCOME**

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State except that if such income is derived from sources in the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

Article 23**ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION**

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In the case of Malaysia, double taxation shall be eliminated as follows:

Subject to the laws of Malaysia regarding the allowance as a credit against Malaysian tax of tax payable in any country other than Malaysia, tax paid in India under the taxation laws of India by a resident of Malaysia in respect of income derived from India shall be allowed as a credit against tax payable in Malaysia in respect of that income. Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Malaysia and which owns not less than 10 per cent of the voting shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account tax paid in India by that company in respect of its income out of which the dividend is paid. The credit shall not, however, exceed that part of the Malaysian tax, as computed before the credit is given, which is attributable to such item of income.

3. For the purposes of paragraph 2, the term "tax paid in India" shall be deemed to include the tax which would, under the laws of India and in accordance with this Agreement, have been payable on any income derived from sources in India had the income not been taxed at a reduced rate or exempted from Indian tax in accordance with the provisions of this Agreement and the special incentives under the Indian laws for the promotion of economic development of India which were in force at the date of signature of this Agreement or any other provisions which may subsequently be introduced in India in modification of, or in addition to, those laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character.

4. In the case of India, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Malaysia, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the amount of tax paid in Malaysia whether directly or by deduction at source. Such amount shall not, however, exceed that part of the tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Malaysia.

5. For the purposes of paragraph 4, the term "tax paid in Malaysia" shall be deemed to include the tax which would, under the laws of Malaysia and in accordance with this Agreement, have been payable on any income derived from sources in Malaysia had the income not been taxed at a reduced rate or exempted from Malaysian tax in accordance with the provisions of this Agreement and the special incentives under the Malaysian laws for the promotion of economic development of Malaysia which were in force at the date of signature of this Agreement or any other provisions which may subsequently be introduced in Malaysia in modification of, or in addition to, those laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character.

Article 24**NON-DISCRIMINATION**

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. Further, this provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.
3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.
4. Nothing in this Article shall be construed so as to prevent either Contracting State from limiting to its nationals the enjoyment of tax incentives designed to promote economic development in that State.
5. In this Article, the term "taxation" means taxes to which this Agreement applies.

Article 25**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the taxation laws of those States, present his case to the competent authority of the State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of reaching an agreement in the preceding paragraphs.

Article 26**EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information including documents as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement, or for the prevention or detection of evasion or avoidance of taxes covered by this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities (including a court, an administrative body or reviewing authority) involved in the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of this Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement .

2. This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Agreement shall have effect:

- (a) in Malaysia:
 - (i) in respect of Malaysian tax, other than petroleum income tax, to tax chargeable for any year of assessment beginning on or after the

first day of January in the calendar year following the year in which this Agreement enters into force;

- (ii) in respect of petroleum income tax, to tax chargeable for any year of assessment beginning on or after the first day of January of the second calendar year following the year in which this Agreement enters into force; and
- (b) in India:
 - in respect of income in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

4. The Agreement between the Government of Malaysia and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at New Delhi, India on the 25th day of October 1976 shall cease to have effect when the provisions of this Agreement become effective in accordance with the provisions of paragraph 3.

Article 29

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect:

- (a) in Malaysia:

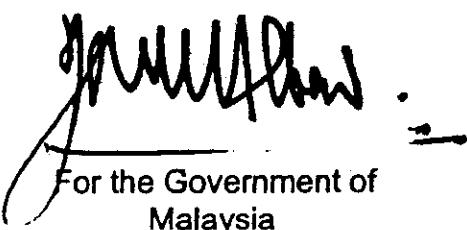
- (i) in respect of Malaysian tax, other than petroleum income tax, to tax chargeable for any year of assessment beginning on or after the first day of January in the calendar year following the year in which the notice is given;
- (ii) in respect of petroleum income tax, to tax chargeable for any year of assessment beginning on or after the first day of January of the second calendar year following the year in which the notice is given; and

(b) in India:

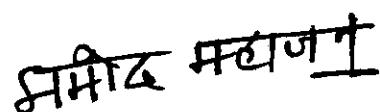
in respect of income arising in any fiscal year on or after the 1st day of April next following the date on which the notice is given.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised thereto, by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Putrajaya this 14th day of May 2001, each in Malay, Hindi and English language, all texts being equally authentic. In the event of there being a dispute in the interpretation and the application of this Agreement, the English text shall prevail.



For the Government of
Malaysia



STATE SECRETARY

For the Government of
the Republic of India

PROTOCOL

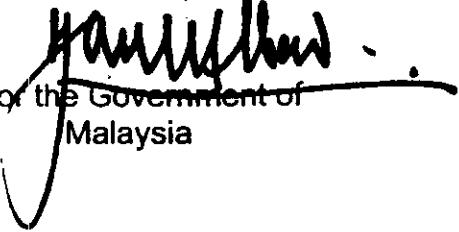
At the time of signing the Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

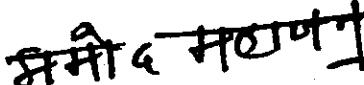
It is understood that :

1. For the purposes of the Agreement, the term "fiscal year" wherever it appears means:
 - (i) in the case of Malaysia, the meaning as assigned by section 20 of the Income Tax Act 1967;
 - (ii) in the case of India, the "previous year" as defined under section 3 of the Income Tax Act 1961.
2. With reference to paragraph 1(j) of Article 3, the tax shall not include any amount which is payable by way of a penalty or fine for any default or omission in relation to taxes to which this Agreement applies or which represents any other penalty or fine imposed relating to those taxes.

3. With reference to paragraph 7 of Article 5, the term "arm's length conditions" means the conditions which would have been made or imposed between two enterprises in their commercial or financial relations which would not have differed from those which would have been made or imposed between independent enterprises.
4. With reference to paragraph 1 of Article 6, this paragraph should not be construed as preventing the country of residence to also tax the income under this Article.
5. With reference to subparagraphs 3(a)(i) and (ii) of Article 28 and subparagraphs a(i) and (ii) of Article 29, the term "year of assessment" has the meaning assigned to under section 2 of the Income Tax Act 1967.

DONE in duplicate at Putrajaya this 14th day of May 2001, each in the Malay, Hindi and English language, all texts being equally authentic. In the event of there being a dispute in the interpretation and the application of this Agreement, the English text shall prevail.


For the Government of
Malaysia



For the Government of
the Republic of India

[Notification No. 257/2004/F. No. 506/123/84-FTD]

POONAM DUTT, Jt. Secy.